

8-11-97. SOURCES OF INTERNATIONAL LAW. →

अंतर्राष्ट्रीय विधि के

स्रोतों के संबंध में विधिवैकाओं तथा विद्वानों के बीच मतभिन्नता पाई जाती है। विभिन्न न्यायिक निर्णयों में भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों के विभिन्न प्रकार एवं संख्या के संबंध में भिन्न-2 विचार व्यक्त किए गए हैं। Oppenheim तथा O'Connell ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों का उल्लेख किया है। Starke ने सामान्य रूप से स्वीकृत स्रोतों से अलग एक स्रोत का भी उल्लेख किया है। Norwegian Claims Case में Permanent Court of Arbitration ने (i) Treaties, (ii) Customs, (iii) General principle of law recognised by the civilised nations तथा (iv) न्यायिक निर्णयों को अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में स्वीकार किया। 1927 के Lotus Case में P.C.J. ने पहले तीन स्रोतों को ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में स्वीकार किया। परन्तु आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय विधि के पाँच स्रोतों का स्वीकार किया जाता है। इनमें से संविधियों, प्रथाओं तथा कानून के सामान्य सिद्धांतों को प्रमुख स्रोत तथा न्यायिक निर्णयों तथा विधिवैकाओं के ग्रंथों को सहायक स्रोत कहा जा सकता है।

उपरोक्त पाँचों स्रोतों को उ.स.ज.

की संविधि की 38 वीं धारा में महत्व के लिहाज से व्यवस्थित रूप से रखा गया है। इसी शब्दों में, उ.स.ज. की Statute (1) Treaties and Conventions, (2) Customs, (3) General Principles of Law recognised by the civilised nations, (4) न्यायिक निर्णय एवं (5) विधिवैकाओं के ग्रंथ एवं उल्लेख को अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में स्वीकार करती है।

Customs : —

प्रकारें हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रारंभिक एवं प्राचीनतम स्रोत हैं, इसलिए विभिन्न स्रोतों के उल्लेख को प्रथाओं के उल्लेख से ही शुरू किया जाया। 19 वीं सदी के अंत तक प्रथाओं को ही अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रारंभिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता था।

अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में प्रथाओं को समझने के लिए प्रथाओं एवं व्यवहारों के बीच अंतर एवं उनके बीच पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करना आवश्यक होगा। प्रथा आचरण करने के ऐसी स्पष्ट एवं सतत स्वभाव को कहते हैं जिसका विकास इस विश्ववास के अंतर्गत हुआ है कि यह आचरण अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार अनिवार्य अथवा उचित है, जबकि व्यवहार के साथ ऐसा नहीं है। इसके अतिरिक्त, व्यवहार आचरण के स वैसे स्वभाव को कहते हैं जो अपने निर्माण के प्रांशिक चरण में होते हैं और विश्व के अधिकांश देशों या सभी राज्यों द्वारा उ-हे सामान्य रूप से नहीं माना जाता जबकि प्रथाएँ अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ होती हैं और इसके विकसित रूप में होने के चलते विश्व के अधिकांश देश उन्हें मानते हैं।

प्रथा के निष्पारण के लिए सामान्यतः पाँच साधनों का सहारा लिया जाता है :- (i) संयुक्त राज्यों के विदेश कार्यालयों के वेसं करतविय जिनमें प्रथागत नियमों के संबंध में राज्यों के व्यवहार के प्रमाण निहित होते हैं, (ii) विधितेकाओं के ग्रंथ एवं प्रलेख जिनमें विभिन्न प्रथागत नियमों के विकास की प्रक्रिया की व्याख्या उनके द्वारा की जाती है। (iii) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का व्यवहार, (iv) अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों का व्यवहार तथा (v) राज्यों के विधि न्यायालयों के व्यवहार।

### TREATIES AND CONVENTIONS: —

संधियों को अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रत्यक्ष स्रोत कहा जा सकता है। P.C.U.C. ने Wimbledon Case में निर्णय देते हुए अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में संधियों को प्राथमिकता दी।

अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत की दृष्टि से संधियों को उग लो गणों में बाँट सकते हैं - Lawmaking treaties तथा, Treaty Contracts. अंतर्राष्ट्रीय विधि की दृष्टि से बहुपक्षीय विधिकारी संधियों को ही प्रथम स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है क्योंकि इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि के बहुत से नियमों को निरूपित किया जाता है। परन्तु बहुपक्षीय संधियों का विधायी महत्त्व या प्रभाव

इस बात में निहित होता है कि बड़ी संख्या में राष्ट्रों के पक्षधर हों तथा उनमें विश्व के लगभग सभी महान राष्ट्र सम्मिलित हों। ऐसी विधिकारी संधियों में 1856 का Paris Conventions, 1874 का Universal Postal Union Convention, 1899 तथा 1907 के Hague Conventions, 1919 का League Covenant, 1930 का Geneva Conventions, 1945 का U.N. Charter, 1949 का Geneva Conventions, 1982 की Sea Law Treaty आदि का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता सकता है।

संधि अनुबंधों को अंतरराष्ट्रीय विधि का प्रचलन प्राप्त नहीं करा जा सकता, परंतु ये संधियाँ भी अंतरराष्ट्रीय विधि के विकास में सहायक सिद्ध हुई हैं।

General Principle of Law: — अब तक न्यायालयों

द्वारा जिस प्रकार कानून के सामान्य सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कानून के सामान्य सिद्धांत वैसे सिद्धांत हैं जिन्हें सम्यक् राज्य अपनी विधि व्यवस्थाओं में मान्यता प्रदान करते हैं और साथ ही साथ उन सिद्धांतों को राज्यों के मध्य के पारस्परिक संबंधों में भी लागू किए जाते हैं।

इस प्रकार यद्यपि प्रथाओं से सिद्धांतों को मुश्किल से ही अलग किया जा सकता है, परंतु यह ध्यान देने योग्य है कि ये सामान्य सिद्धांत प्रथाओं से मूलतः गिन्न हैं। यह गिन्नता कुछ न्यायिक निर्णयों पर दृष्टि डालने से भी स्पष्ट हो जाती है। ऐसे निर्णयों में Charzow Factory Case - 1927, Mavrommatis Palestine Concessions Case तथा Naulilla Case में P.C.J. तथा P.C.A. के निर्णयों को रखा जा सकता है।

Law Determining Agencies: —

विधि निष्पत्तिक अभिकरणों में न्यायिक निर्णयों का महत्त्व अधिक है निःसंदेह न्यायालय का कार्य विधिके अनुसार निर्णय

करना होता है, विधि विमलित करना नहीं। परन्तु विधि की व्याख्या करने में न्यायालय नवीन नियमों का प्रतिपादन भी कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों तथा राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में किये गए निर्णयों का विधि के नियम के विचारण के लिए सहारा लिया जा सकता है। परन्तु कौनों प्रकार के न्यायालयों में अधिक महत्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के निर्णय को दिया जाता है। विधिवेत्ताओं के ग्रंथ एवं उल्लेख : —

विधि विचारिक अभिकरणों के रूप में केवल वैसे ही विधिवेत्ताओं एवं विद्वानों के लेखों एवं उल्लेखों को महत्व दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में श्लाघा प्राप्त कर चुके हों। उन ग्रंथों एवं उल्लेखों को सम्पूर्ण राज्य-व्यवहार के प्रमाण के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है यह भी उल्लेखनीय है कि मृत विधिवेत्ताओं एवं विद्वानों के लेखों एवं उल्लेखों से अधिक महत्व दिया जाता है फिर, Territorial विधिवेत्ताओं एवं विद्वानों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से अधिक महत्व Extra Territorial विधिवेत्ताओं एवं विद्वानों के द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का होता है।